एस. एस. सारोन और लिसा गिल, जे. जे.

मुरारी लाल गुप्ता- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

सी. डब्ल्यू. पी. No.9931 साल 2016

1 सितंबर, 2017

क) भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226- हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवा में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश) अधिनियम, 2016- सेक्शन अनुसूची- III के साथ पठित 3 और 4- जनहित याचिका-का दायरा- संविधान की मूल संरचना के विपरीत अधिनियम, 2016 की अनुसूची-III (पिछड़ा वर्ग खंड सी) को रद्द करने और अमान्य करने के लिए की गई प्रार्थना, अधिकार अधिकारातीत, अवमाननापूर्ण, मनमाना, इसके अलावा, शून्य और शून्य होने के कारण-याचिकाकर्ता द्वारा जनहित याचिका में दावा की गई राहत को अस्वीकार कर दिया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि पी. आई. एल. को आम तौर पर किसी विधायी अधिनियम को अमान्य करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना चाहिए और अपनाया जाना चाहिए।न्यायालयों को पी. आई. एल. में

किसी अधिनियम के अधिकारों पर विचार करने में धीमी गति से और सावधानी और सावधानी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। पी. आई. एल. एस. के माध्यम से, 2016 के अधिनियम के अधिनियमन पर हमला किया जाना चाहिए और इस आधार पर अमान्य कर दिया जाना चाहिए कि जिन जातियों को आरक्षण का लाभ दिया गया है, उनकी आवश्यक पहचान नहीं की गई है।हालाँकि, यह इस स्तर पर भी कानून को अमान्य करने की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है।विधायिका के एक विधायी अधिनियम को केवल पूछने पर अमान्य नहीं किया जाना चाहिए।

(पैरा 42)

ख) भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवा में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश) अधिनियम, 2016-एस. एस. अनुसूची-III के साथ पठित 3 और 4-जनहित याचिका-अधिनियम, 2016 की अनुसूची-III (पिछड़ा वर्ग खंड 'सी') को रद्द करने और अमान्य करने के लिए की गई प्रार्थना का दायरा नहीं बनाया गया है, विशेष रूप से जब इस आधार पर हमला किया जाता है कि अनुसूची-III में उल्लिखित जातियों के पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए मात्रात्मक डेटा एकत्र करने का अभ्यास नहीं किया गया है-याचिका का निपटारा कुछ निर्देशों के साथ किया गया है।

माना गया कि 2016 580 को अमान्य करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है अधिनियम, विशेष रूप से जब इस आधार पर हमला करने

की मांग की जाती है कि अनुसूची III में उल्लिखित जातियों के पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए मात्रात्मक डेटा एकत्र करने का अभ्यास नहीं किया गया है।यह अभ्यास इस स्तर पर भी किया जा सकता है।वास्तव में, अनुमत आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए, एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) 8 एस. सी. सी. 212 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यों को प्रशासन में दक्षता बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए वर्ग के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़ों की पहचान करनी होगी और उन्हें एकत्र करना होगा।यदि संबंधित राज्य इसे पहचानने और मापने में विफल रहता है, तो आरक्षण का प्रावधान अमान्य होगा। (पैरा 45)

मुकेश वर्मा, अधिवक्ता,
सी. डब्ल्यू. पी. No.9931 साल 2016 में याचिकाकर्ता के लिए।
वी. के. जिंदल, वरिष्ठ अधिवक्ता,
लाल बहादुर खोवाल, अधिवक्ता के साथ,
और जन्या सिरोही, अधिवक्ता,
सी. डब्ल्यू. पी. नंबर .11064 साल 2016 याचिकाकर्ता के लिए।
पी. आर. यादव, अधिवक्ता
याचिकाकर्ता के लिए सी. डब्ल्यू. पी. No.13125 साल 2016
आर. के. चोपड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता,
गौरव शर्मा, अधिवक्ता के साथ,
सी. डब्ल्यू. पी नंबर 13574 साल 2016 याचिकाकर्ता के लिए।
जगदीप धनखड़, वरिष्ठ अधिवक्ता,
लोकेश सिंहल, एडिशनल।महाधिवक्ता हरियाणा
और सुरेंद्र सिंह पन्नू, डीएजी, हरियाणा
प्रतिवादी के लिए-हरियाणा राज्य।

आर. एस. बद्रान, अधिवक्ता,
और एस. एस. नारा, अधिवक्ता,
सी. डब्ल्यू. पी. नंबर .9931 साल 2016 में प्रतिवादी संख्या 3 के लिए
रमेश हुड्डा, अधिवक्ता,
सी. डब्ल्यू. पी. नंबर 13574 साल 2016 में प्रतिवादी संख्या 3 के लिए।
आर. एस. कुंडू, अधिवक्ता,
सी. डब्ल्यू. पी. नंबर 9931 साल 2016 उत्तरदाताओं के लिए संख्या 4 और 7 के लिए।
जसदेव सिंह मेहंदीरत्ता, अधिवक्ता,
सी. डब्ल्यू. पी. नंबर 13574 साल 2016 में प्रतिवादी संख्या 4 के लिए।

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 9931 साल 2016 में प्रतिवादी सं. 5 के लिए।
अरुण गोसाई, अधिवक्ता, सी. डब्ल्यू. पी. नंबर 13125 साल 2016 में प्रतिवादी संख्या 5- यू. ओ. आई. के लिए केंद्र सरकार के अधिवक्ता कमल शर्मा, अधिवक्ता, और गोबिंद शर्मा, अधिवक्ता,
सी. डब्ल्यू. पी. सं. 13125 साल 2016 में प्रतिवादी सं. 6 के लिए।
संजीव रॉय, अधिवक्ता, आई. पी. एस. दोआबा, अधिवक्ता, भारत संघ के लिए।
संजीव कुमार आर्य, अधिवक्ता,
प्रतिवादी संख्या 8 के लिए-महासभा, करनाल के लिए।जसमेर सिंह रोजेरा, अधिवक्ता,
सी. डब्ल्यू. पी. नंबर 9931 साल 2016 में प्रतिवादी संख्या 9 के लिए।
एस. एन. यादव, अधिवक्ता,
आदित्य यादव, अधिवक्ता और शक्ति सिंह, अधिवक्ता

एस. एस. सारोन, जे.

(1) यह निर्णय और आदेश उपरोक्त चार रिट याचिकाओं का निपटारा करेगा जो मुख्य रूप से हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश) अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 15) ('2016 अधिनियम'-संक्षेप में) की अनुसूची-III (पिछड़ा वर्ग ब्लॉक 'सी') को रद्द करने और अमान्य करने की मांग करती

हैं, जिसमें कहा गया है कि यह संविधान की मूल संरचना के विपरीत है, अधिकार अधिकारातीत, अवमाननापूर्ण, मनमाना है। इसके अलावा, अमान्य होने और void.The अधिनियम को 12.05.2016 पर अधिसूचित किया गया था।

(2) मुरारी लाल गुप्ता के मामले अन्य बातों के साथ साथ, यह अन्य बातों के साथ कहा गया है कि 2016 अधिनियम की अनुसूची III के विवादित प्रावधानों के संदर्भ अन्य बातों के साथ साथ, छह जातियों, यानी जाट, जाट सिख, रोर, बिश्नोई, त्यागी, मुल्ला जाट/मुस्लिम जाट को पिछड़े वर्ग खंड 'सी' घोषित करके आरक्षण प्रदान किया गया है।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह आरक्षण बिना किसी वैध और वैध आधार के है, इसके अलावा, राम सिंह और अन्य बनाम भारत संघ 1 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत है।2016 अधिनियम की अनुसूची III के उक्त प्रावधान, वास्तव में राम सिंह के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करने के बराबर हैं, जो कि प्रस्तुत किया गया है, कानून में अस्वीकार्य है। एक बार दिया गया अंतिम निर्णय तब तक संचालित होता है और तब तक लागू रहता है जब तक कि न्यायालय द्वारा इसे उचित कार्यवाही में परिवर्तित नहीं किया जाता है।फैसले को रद्द करने वाला कानून संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। 2016 अधिनियम की अनुसूची III को न्यायाधीश के. सी. गुप्ता आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अधिनियमित किया गया है, जिसे सेवाओं में और

शैक्षणिक संस्थानों में उनके उत्थान के लिए पर्याप्त आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्गों के पिछड़ेपन की पहचान के लिए स्थापित किया गया था।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि न्यायाधीश के. सी. गुप्ता आयोग की रिपोर्ट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम सिंह के मामले (उपरोक्त) में स्वीकार नहीं किया था। इसके अलावा, विवादित कानून के पारित होने तक उक्त मामले में निर्णय पारित होने के बाद, कोई नया तथ्य सामने नहीं आया था और न ही उन परिस्थितियों में कोई बदलाव हुआ था जो इस तरह के कानून को पारित करने की आवश्यकता होगी।

(3) वास्तव में, इस न्यायालय द्वारा वेद मामले में एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था। प्रकाश और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 9132) 2015) जिसके तहत हरियाणा के राज्यपाल द्वारा बिश्नोई, जाट, जाट सिख, रोर और त्यागी को विशेष पिछड़े वर्ग घोषित करने और सरकारी/सरकारी उपक्रमों और स्थानीय निकायों के साथ-साथ इन विशेष पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए पहले से ही अधिसूचना पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किए गए 27 प्रतिशत आरक्षण को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से रोक लगा दी गई थी।कुछ इसी तरह का आदेश 2014 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 2441 में भी 29.03.2016 पर पारित किया गया था और इस अवधि के दौरान भी परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ था।परिस्थितियों में एकमात्र नया

बदलाव यह रहा है कि हिंसक आंदोलनों की घटनाएँ और अधिक हिंसक आंदोलनों की पुनरावृत्ति की धमकियाँ थीं जिन्हें विवादित अधिनियम पारित किया गया था।तथ्यात्मक स्थिति यह थी कि हरियाणा राज्य विधानमंडल के पास 2016 के अधिनियम की अनुसूची III में उल्लिखित उपरोक्त छह जातियों के पिछड़ेपन के बारे में कोई जानकारी या सामग्री नहीं थी। राम सिंह के मामले (ऊपर) में फैसले का खंडन या संदेह करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी।इसलिए, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 2016 अधिनियम की अनुसूची III को लागू करने की विधायी कवायद राम सिंह के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने के बराबर है।विवादित कानून तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए 10 प्रतिशत और प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए 6 प्रतिशत तक आरक्षण देता है, इसके अलावा, 2016 अधिनियम की अनुसूची III में उल्लिखित छह जातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण है।

(4) कुम्हार महासभा में कुम्हार धर्मशाला बनाम **हरियाणा राज्य (2016 का सी. डब्ल्यू. पी. No.11064) के लिए एक समान चुनौती** 2016 के अधिनियम की अनुसूची III बनाई गई है, जिसके संदर्भ में पिछड़े वर्ग ब्लॉक-सी के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है, जो यह कहा गया है कि अवमाननापूर्ण, मनमाना, अमान्य और अमान्य है; इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के साथ-साथ राम सिंह के

मामले (उपरोक्त) और इंद्र में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का भी उल्लंघन है। **साहनी बनाम भारत संघ 2.(5) यादव कल्याण सभा बनाम हरियाणा राज्य (सी. डब्ल्यू. पी. नं.** 13125 2016), न्यायाधीश के. सी. गुप्ता आयोग द्वारा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई दिनांक 1 की रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया गया है।इसके अलावा, हरियाणा सरकार द्वारा न्यायाधीश के. सी. गुप्ता आयोग की सिफारिशों पर सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को 10 प्रतिशत ऊर्ध्वाधर आरक्षण देने के लिए जारी की गई अधिसूचना और दिनांकित निर्देशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) में निहित प्रावधानों के विपरीत और इंद्र साहनी के मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत अवैध बताते हुए हमला किया गया है।2016 के अधिनियम की अनुसूची III को रद्द करने और राज्य को विवादित कानून के अनुसार पदों पर नियुक्तियां नहीं करने का निर्देश देने के लिए इसी तरह की एक और प्रार्थना की गई है।

(6) सतवीर सिंह सैनी और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2016 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 13,574), हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की दिनांकित रिपोर्ट, अर्थात न्यायाधीश के. सी. गुप्ता आयोग की रिपोर्ट को रद्द करने के लिए एक प्रार्थना की गई है, और 2016 का अधिनियम भी अवैध और मनमाना है जैसा कि राम सिंह के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा पहले ही माना जा चुका है।एक और प्रार्थना की गई है कि हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के संविधान के साथ-साथ 2016 के अधिनियम को अमान्य घोषित किया जाए।

(7) मुरारी लाल गुप्ता के मामले (2016 का सी. डब्ल्यू. पी. No.9931) में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के हरियाणा सरकार के विशेष सचिव श्री शेखर विद्यार्थी का लिखित बयान दायर किया गया है।यह कहा गया है कि वर्तमान जनहित याचिका प्रामाणिक नहीं थी और निहित स्वार्थों से प्रेरित बाहरी परिस्थितियों से प्रेरित थी।विशेष पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के मुद्दे को हल करने के लिए आंदोलन के मद्देनजर, हरियाणा के मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय समिति का गठन दिनांक 1 के आदेश द्वारा किया गया था।उक्त समिति ने विभिन्न उल्लिखित तिथियों पर बैठकें और प्रासंगिक मुद्दों पर विस्तार से विचार किया गया।समिति के समक्ष उपलब्ध सभी सूचनाओं और सामग्री का अध्ययन करने के बाद, उक्त समिति द्वारा आरक्षण का लाभ दिए जाने के लिए छह समुदायों को शामिल करने के लिए सरकार को सिफारिशें की गईं।

(8) लिखित बयान में कहा गया है कि इस मामले की जांच राज्य सरकार और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (उत्तरदाता संख्या 1 और 2) द्वारा की गई थी।न्यायाधीश के. सी. गुप्ता आयोग की सिफारिशों और नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों

की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने और नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में सेवाओं में नियुक्तियों में आरक्षण के प्रावधान करने के लिए राज्य को सक्षम बनाने वाले प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, एक विधेयक अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था।अनुमोदन के बाद, हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान आदेश के लिए इसे हरियाणा राज्य विधानसभा में रखा गया था।विधेयक पारित किया गया और आरक्षण दिया गया।

(9) यह आगे कहा गया है कि राम सिंह के मामले (उपरोक्त) में, यह मामला हरियाणा सहित नौ राज्यों के अन्य पिछड़े वर्गों ('ओ. बी. सी.'-संक्षेप में) को ओ. बी. सी. की केंद्रीय सूची में शामिल करने से संबंधित था। विवादित 2016 का अधिनियम हरियाणा राज्य के पिछड़े वर्गों को राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने से संबंधित है।सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को केंद्र सरकार द्वारा जाट समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल करने के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।न्यायाधीश के. सी. गुप्ता आयोग की रिपोर्ट की टिप्पणियां इसी संदर्भ में और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ('एन. सी. बी. सी.'-संक्षेप में) के निष्कर्षों के आधार पर हैं।वास्तव में, एन. सी. बी. सी. ने सर्वेक्षण का कार्य भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ('आई. सी. एस. एस. आर.'-संक्षेप में) द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति को सौंपा था और आई.

सी. एस. एस. आर. की रिपोर्ट से पता चला कि जाट समुदाय स्कूल और उच्च शिक्षा नामांकन दोनों में पीछे है।यह भी पाया गया कि पाँच से सत्रह वर्ष की आयु के बारह प्रतिशत जाट बच्चे कभी स्कूल नहीं गए थे, जो कई अन्य पिछड़ा वर्ग से अधिक था। स्नातक स्तर पर जाटों का नामांकन लगभग 6.5 प्रतिशत था, जो 8.3 प्रतिशत के औसत स्तर से कम था।स्नातकोत्तर स्तर पर जाटों का नामांकन औसतन 2.26 प्रतिशत के मुकाबले 1.7 प्रतिशत था।इसलिए, यह तर्क दिया जाना चाहिए कि 2016 का अधिनियम को लेने के बाद वैध रूप से पारित किया गया था ध्यान में रखने योग्य प्रासंगिक कारक।(10) प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से हरियाणा कर्मचारी चयन समिति के सचिव (कानूनी) श्री राजीव दुदेजा द्वारा 2016 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 13125 में संक्षिप्त जवाब दाखिल किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता न्यायाधीश के. सी. गुप्ता आयोग द्वारा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित दिनांकित रिपोर्ट को दरकिनार करने के लिए प्रार्थना करता है, हरियाणा सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को 10 प्रतिशत ऊर्ध्वाधर आरक्षण देने के लिए जारी अधिसूचना न्यायाधीश के. सी. गुप्ता आयोग की सिफारिशों और दिनांकित निर्देशों पर है।यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा हरियाणा राज्य को दिनांकित 27.09.2013 और 15.07.2014 अधिसूचना के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में नियुक्तियां नहीं करने

का निर्देश देने के लिए एक और अनुरोध किया गया है।हरियाणा राज्य चयन आयोग, यह प्रस्तुत किया जाता है, केवल एक भर्ती एजेंसी है और संबंधित विभागों द्वारा भेजी गई आवश्यकताओं और प्रासंगिक सेवा नियमों के अनुसार भर्ती करती है।पदों का विभाजन भी विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है।यह विभिन्न विभागों से मांग की प्राप्ति पर है कि हरियाणा राज्य चयन आयोग ने विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए विज्ञापन संख्या 5/2016 जारी किया और यह जानबूझकर नहीं किया गया जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था।उक्त विज्ञापन में कुल 47 श्रेणियों के पदों का विज्ञापन किया गया था और इनमें से 13 श्रेणियों के पदों, सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किया गया था।इन 13 श्रेणियों के पदों में से, जिनमें सामान्य श्रेणी के आरक्षण में आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति शामिल थे, 6 श्रेणियों के पदों का पुनः विज्ञापन किया गया था, जिन्हें पहले विज्ञापन No.2/2013 के खिलाफ विज्ञापित किया गया था। मत्स्य अधिकारी, सांख्यिकीय सहायक/निरीक्षक (एन. एस. एस.)/अन्वेषक, कनिष्ठ क्षेत्र अन्वेषक, सहायक ड्राफ्ट्समैन (सिविल), ट्रेसर सिविल (मुख्यालय) और चार्ज-मैन और जिसमें पहले से ही सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद थे और शेष पदों के लिए पहली बार विज्ञापन दिया गया था।

(11) मुरारी लाल गुप्ता के मामले में धर्म पाल, अध्यक्ष, मुल्ला जाट संघर्ष समिति, हरियाणा, गाँव केरबा, तहसील इंद्री, जिला करनाल (प्रतिवादी संख्या 5) द्वारा भी जवाब दाखिल किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि पैरा संख्या 8 (एस. सी. सी. के) में राम सिंह के मामले (उपर्युक्त) में यह उल्लेख किया गया है कि एन. सी. बी. सी. ने यह विचार रखा था कि चूंकि उसके पास इस मामले में पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं है, इसलिए आई. सी. एस. एस. आर. से 586 पर एक व्यापक साहित्य सर्वेक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का अनुरोध किया जाना चाहिए। आसन्न अभ्यास के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र आदेश के लिए विषय।इसके बाद, एन. सी. बी. सी. ने जाट समुदाय को शामिल करने के पक्ष और विपक्ष में अभ्यावेदन सहित इस संबंध में प्राप्त सभी रिपोर्टों/दस्तावेजों को आई. सी. एस. एस. आर. को भेज दिया। आई. सी. एस. एस. आर. द्वारा गठित विशेषज्ञ निकाय ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो मुख्य रूप से संबंधित राज्यों की ओ. बी. सी. सूची में जाट समुदाय को शामिल करने के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों को प्रस्तुत विभिन्न राज्य आयोगों की रिपोर्टों पर आधारित थी।जाहिरा तौर पर, आई. सी. एस. एस. आर. ने पुस्तकों/साहित्य/अभ्यावेदन के माध्यम से अन्य सामग्रियों का कोई अध्ययन नहीं किया। उल्लेखनीय है कि आई. सी. एस. एस. आर. की रिपोर्ट में कोई सिफारिश नहीं की गई थी, बल्कि केवल मौजूदा तथ्यों को निर्धारित किया गया था।इसके बाद एन. सी. बी.

सी. ने अपनी कई बैठकों में आई. सी. एस. एस. आर. की उक्त रिपोर्ट पर चर्चा की।इसके साथ ही, एन. सी. बी. सी. ने संबंधित राज्यों की राजधानियों में सार्वजनिक सुनवाई तय करने के लिए राज्य सरकारों को पत्र लिखे।चूंकि इस संबंध में राज्यों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, इसलिए एन. सी. बी. सी. ने दावों और जवाबी दावों (आपत्तियों) की सुनवाई के लिए अलग-अलग तारीखें तय करते हुए सार्वजनिक सुनवाई करने के लिए नोटिस प्रकाशित किए।फरवरी, 2014 में नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में दो तारीखों पर सार्वजनिक सुनवाई होनी थी।

(12) उपरोक्त से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. सी. बी. सी. विशेषज्ञों का एक निकाय नहीं था जैसा कि पैरा 847 में इंदिरा साहनी के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिकल्पित किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया था कि निकाय को आधिकारिक और गैर-आधिकारिक दोनों क्षेत्र के विशेषज्ञों से बना होना था और एक उचित और प्रभावी जांच करने के लिए आवश्यक शक्तियों के साथ निहित किया जाना था।हालांकि, एन. सी. बी. सी. ने खुद स्वीकार किया था कि उसके पास कोई विशेषज्ञता नहीं है।इसलिए, एन. सी. बी. सी. या उसके गठन द्वारा तैयार की गई किसी भी रिपोर्ट पर की गई कोई भी कार्रवाई इंद्र साहनी के मामले (उपरोक्त) का उल्लंघन थी।

(13) इन परिस्थितियों में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी आयोग की रिपोर्ट पर कोई निर्भरता नहीं रखी जा सकती है जो अन्यथा कानून के

अनुसार गठित नहीं किया गया था।इसके कार्य अधिकार क्षेत्र के बिना थे।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि हरियाणा राज्य ने 2016 के अधिनियम को पारित करते समय धारा 5 में एक विशेष प्रावधान किया था कि पिछड़े खंडों के "क्रीमी लेयर" से संबंधित किसी भी व्यक्ति को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।इसके अलावा, 2016 अधिनियम की खंड 13 में 'अनुसूची' के संशोधन के लिए एक प्रावधान किया गया है।राज्य सरकार, उक्त खंड 13 के संदर्भ में, 2016 अधिनियम के लागू होने के दस साल की समाप्ति पर और उसके बाद की प्रत्येक दस साल की अवधि में, अनुसूची का संशोधन करेगी। निर्णयों को उद्धृत किया गया है और रिट याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना की गई है।

(14) इन मामलों में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताोें द्वारा उठाए गए तर्क मुख्य रूप से इस प्रभाव के लिए हैं कि 2016 अधिनियम की अनुसूची III में उल्लिखित समुदायों/जातियों में से जाट समुदाय के लिए सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में दिया गया आरक्षण अत्यधिक मनमाना है क्योंकि राज्य सेवाओं में उनका पर्याप्त और पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।राज्य सेवाओं में जाट समुदाय के सदस्यों द्वारा रखे गए पदों का विवरण उल्लेख किया गया है, जो कहा जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत हरियाणा राज्य के विभिन्न कार्यालयों से एकत्र किए गए हैं।यह प्रस्तुत किया जाता

है कि हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ('हरियाणा बी. सी. आयोग'-संक्षेप में) ने सर्वेक्षण के उद्देश्य से हरियाणा राज्य के 157 गाँवों का चयन किया है।इन 157 गाँवों के चयन के मानदंड का खुलासा नहीं किया गया था।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इन गाँवों को जानबूझकर बाहरी कारणों से चुना गया था।हरियाणा बी. सी. आयोग ने वास्तव में ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केंद्र ('सी. आर. आर. आई. डी.'-संक्षेप में) को दिनांकित 06.02.2012 पत्र के माध्यम से काम सौंपा।सी. आर. आर. आई. डी. ने एक सर्वेक्षण किया और 01.03.2012 से 31.03.2012 तक डेटा एकत्र किया।हरियाणा बी. सी. आयोग ने सर्वेक्षण करने का काम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक को दिनांकित 27.04.2012 पत्र के माध्यम से दिया।यह आरोप लगाया जाता है कि उक्त विश्वविद्यालय ने सर्वेक्षण को बेहद लापरवाही से किया।सर्वेक्षण के संचालन में अनियमितताएं की गईं।जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले खज़ान सिंह सांगवान को परियोजना निदेशक नियुक्त किया गया।यह तर्क दिया जाता है कि किए जाने वाले सर्वेक्षण के संबंध में सर्वेक्षणकर्ताओं को कोई संकेतक नहीं दिए गए थे।वास्तव में, कोई प्रभावी सर्वेक्षण नहीं किया गया था।किसी भी मामले में, हरियाणा बी. सी. आयोग ने 12.12.2012 पर अनुचित और गैरकानूनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

(15) राम सिंह के मामले (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार किया गया था।यह तर्क दिया जाता है कि न्यायाधीश के.

सी. गुप्ता आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को राम सिंह के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।हालाँकि, अब न्यायाधीश के. सी. गुप्ता आयोग की वही रिपोर्ट, जिसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था, पर फिर से भरोसा किया गया है और 2016 के अधिनियम की अनुसूची III को पारित करते समय उस पर विचार किया गया है। इसलिए, इसे अमान्य किया जा सकता है क्योंकि कोई नई सामग्री या रिपोर्ट एकत्र नहीं की गई थी।यह भी तर्क दिया जाता है कि किसी भी मामले में विवादित कानून, यानी 2016 अधिनियम, 588 द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण यह इंदिरा साहनी के मामले (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करता है क्योंकि आरक्षण की ऊपरी सीमा का 50 प्रतिशत उल्लंघन किया गया है।

(16) जवाब में, प्रतिवादी की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं का यह रुख कि राज्य विधान राम सिंह के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत है, मान्य नहीं है।उक्त मामले में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती केवल भारत के राजपत्र में प्रकाशित केंद्र सरकार की अधिसूचना के लिए थी, जिसके द्वारा जाट समुदाय को विभिन्न राज्यों की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया था।न्यायाधीश के. सी. गुप्ता आयोग की रिपोर्ट को उक्त मामले में चुनौती नहीं दी गई थी। इसके अलावा, किसी भी राज्य में राज्य स्तर पर जाट समुदाय को दिए गए आरक्षण को कोई चुनौती नहीं

दी गई थी।उच्चतम न्यायालय के समक्ष राम सिंह के मामले (उपरोक्त) में मुख्य मुद्दा यह था कि एन. सी. बी. सी. द्वारा दी गई सलाह/सिफारिश को केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लेने में क्या महत्व दिया जाना चाहिए, जो एक महत्वपूर्ण निर्धारण था जिसे न्यायालय को करने की आवश्यकता थी।केंद्र सरकार ने बिना कोई कारण बताए एन. सी. बी. सी. की रिपोर्ट से असहमति जताई।न्यायालय ने न्यायाधीश के. सी. गुप्ता आयोग की रिपोर्ट के संबंध में केवल एन. सी. बी. सी. के प्रतिबिंब और धारणा पर विचार किया।इसलिए, प्रतिवादी के अनुसार, उक्त रिपोर्ट राम सिंह के मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कभी भी विचाराधीन नहीं थी।राम सिंह के मामले (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय के फैसले में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके द्वारा राज्य कानून नहीं बना सकता है।इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई दलीलें आधारहीन हैं, इसके अलावा, योग्यता से रहित हैं क्योंकि आरक्षण प्रदान करने वाले कानून को अमान्य नहीं किया जा सकता है।किसी भी मामले में, राम सिंह के मामले में फैसला राज्य स्तर पर जाट जाति को आरक्षण प्रदान करने से संबंधित नहीं है।

(17) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है द्वारा मामलों के अभिलेखों को देखा है।

(18) जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, इन याचिकाओं में चुनौती मुख्य रूप से 2016 के उस अधिनियम को दी गई है जिसे हरियाणा विधानमंडल

ने हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करने के लिए पारित किया है।2016 के अधिनियम की प्रस्तावना अन्य बातों के साथ साथ अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः "हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को सेवाओं में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करना। क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड (4) राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड (5) राज्य को कानून द्वारा नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है, जहां तक कि ऐसे विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या बिना सहायता प्राप्त निजी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित हैं और क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 16 का खंड (4) राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान करने में सक्षम बनाता है, जो राज्य की राय में, राज्य

के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है; और क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 38 के खंड (1) में यह प्रावधान है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से सुरक्षित और संरक्षित आदेशके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास आदेशेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्यायाधीश राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित आदेशेगा और जहां संविधान के अनुच्छेद 38 के खंड (2) में प्रावधान है कि राज्य विशेष रूप से आय में असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा; और जहां संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत, राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हित को विशेष ध्यान से बढ़ावा देगा, और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। और जहाँ हरियाणा राज्य ने राज्य द्वारा सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है; और जहाँ हरियाणा राज्य की राय है कि राज्य में नागरिकों के पिछड़े वर्गों को राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और इसलिए, राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है।”

(19) 2016 अधिनियम की खंड 2 'परिभाषाओं' और खंड 2 (बी), (डी) और (एच) से संबंधित है, जो वर्तमान याचिकाओं के लिए प्रासंगिक होगी, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है:-

“2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, - (ख) "पिछड़े वर्ग" से अनुसूची I, II या III में निर्दिष्ट नागरिकों के ऐसे वर्ग अभिप्रेत हैं;

(घ) "क्रीमी लेयर" से पिछड़े वर्गों के भीतर व्यक्तियों का ऐसा वर्ग अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे;

(ज) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संबद्ध अनुसूचियाँ अभिप्रेत हैं। "

(20) 2016 अधिनियम की धारा 3,4,5,6,13,14 और 15, जो भी प्रासंगिक हैं, निम्नानुसार पढ़िए:-

“3. सेवाओं में आरक्षण:- नियुक्ति करते समय अनुसूची में निर्दिष्ट पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षण किया जाएगा।

4. शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण:- शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश देते समय अनुसूची में निर्दिष्ट पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षण किया जाएगा।

5. मलाईदार परत के संबंध में प्रतिबंध:-

(1) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित कोई भी व्यक्ति नहीं होगा -

(क) शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए विचार किया गया अनुसूची में निर्दिष्ट पिछड़े वर्गों के लिए उसमें आरक्षित सीटों के विरुद्ध; या

(ख) अनुसूची में निर्दिष्ट पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों के खिलाफ राज्य के तहत सेवाओं में आरक्षण का दावा करने या नियुक्ति के लिए विचार करने का हकदार है।(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा, सामाजिक, आर्थिक और ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखने के बाद, जो उचित समझे जाते हैं, पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के बहिष्करण और पहचान के लिए मानदंड निर्दिष्ट करेगी।

(3) उप-धारा (2) के तहत निर्धारित मानदंडों की हर तीन साल में समीक्षा की जाएगी।

6. क्षैतिज आरक्षणः- इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, राज्य सरकार पिछड़े वर्गों के भीतर व्यक्तियों की ऐसी श्रेणी या श्रेणियों के लिए क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, जो वह समय-समय पर आवश्यक समझे।

13. अनुसूची की समीक्षाः- सरकार इस अधिनियम के लागू होने से दस वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद की प्रत्येक दस वर्ष की अवधि में अनुसूची का संशोधन करेगी।

14. प्रबल प्रभावः- इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव होगा, इसके बावजूद कि उस समय लागू किसी अन्य राज्य कानून या किसी ऐसे कानून के आधार पर प्रभावी किसी दस्तावेज में कुछ भी असंगत है।

15. सत्यापनः- किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के लागू होने की तारीख को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और पिछड़े वर्गों की सेवाओं में नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा किया गया आरक्षण और ऐसे आरक्षण के आधार पर की गई कोई भी कार्रवाई या कोई भी कार्रवाई, सभी उद्देश्यों के लिए, कानून के अनुसार वैध रूप से की गई, की गई या की गई मानी जाएगी, जैसे कि यह अधिनियम सभी भौतिक समय पर लागू था जब ऐसा आरक्षण किया गया था और ऐसा काम किया गया था या कार्रवाई की गई थी।"

(21) अनुसूची III, जो 2016 592 की धारा 3 और 4 से संबंधित है अधिनियम और वर्तमान याचिका में आक्षेप किया गया है, जो इस प्रकार हैः-

"अनुसूची-III

(खंड 3 और 4) बैकवर्ड क्लास ब्लॉक 'सी' देखें।1. जाट

2. जाट सिख

3. रोर

4. बिश्नोई

5. त्यागी

6. मुल्ला जाट/मुस्लिम जाट

* सेवाओं में आरक्षणः- तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए दस प्रतिशत और प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए छह प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

* प्रवेश में आरक्षणः- शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।"

(22) उपरोक्त 2016 अधिनियम के अवलोकन से पता चलता है कि यह हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है।'धारा 2 (बी) में पिछड़े खंडों को अनुसूची I, II या III में निर्दिष्ट नागरिकों के ऐसे खंड के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुसूची III में जिन जातियों का उल्लेख किया गया है, वे जाट, जाट सिख, रोर, बिश्नोई, त्यागी और मुल्ला जाट/मुस्लिम जाट हैं। ऐसी जातियों के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए सेवाओं में दस प्रतिशत और प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों में छह प्रतिशत तक आरक्षण है।इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में दस प्रतिशत आरक्षण है।एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि 'क्रीमी लेयर' को पिछड़े खंडों के भीतर व्यक्तियों के ऐसे खंड के रूप में परिभाषित किया

गया है जिसे राज्य सरकार 2016 के अधिनियम के उद्देश्यों के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है। हरियाणा राज्य सरकार ने 2016 के अधिनियम की धारा 2 (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना दिनांक 17.08.2016 जारी की है जो इस प्रकार है:-

"अधिसूचना 17 अगस्त, 2016

सं. 808-एस. डब्ल्यू. (1)।- हरियाणा पिछड़ा खंड (सेवा में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश) अधिनियम, 2016 (2016 का 15) की धारा 2 के खंड (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल ने अधिनियम में संलग्न अनुसूचियों, अर्थात् अनुसूची I, II और III के अनुसार पिछड़े खंडों के भीतर क्रीमी लेयर के बहिष्करण के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्दिष्ट किए हैं।

तीन लाख रुपये तक की सकल वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के बच्चों को सबसे पहले सेवाओं में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का लाभ मिलेगा।बचा हुआ कोटा नागरिकों के पिछड़े वर्गों के उस वर्ग को जाएगा जो तीन लाख रुपये से अधिक लेकिन प्रति वर्ष छह लाख रुपये तक कमाते हैं।प्रति वर्ष छह लाख रुपये से अधिक आय वाले पिछड़े खंडों के खंडों को उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत क्रीमी लेयर माना जाएगा।

टी. सी. गुप्ता, हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।"

(23) उपरोक्त अधिसूचना के अवलोकन से पता चलता है कि अनुसूचि I, II और III में उल्लिखित पिछड़े वर्गों के भीतर मलाईदार परत के बहिष्कार के लिए एक मानदंड प्रदान किया गया है। एक लाख रुपये तक की सकल आय वाले व्यक्तियों के बच्चे। शैक्षणिक संस्थानों में सेवाओं और प्रवेश में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले 3 लाख रुपये दिए जाते हैं।बचा हुआ कोटा नागरिकों के पिछड़े वर्गों के उस वर्ग को दिया जाता है जो रुपये से अधिक कमाते हैं। 3 लाख लेकिन रु। 6 लाख प्रति वर्ष।रुपये से अधिक आय वाले पिछड़े खंडों के खंड। 2016 अधिनियम की धारा 5 के तहत 6 लाख रुपये को मलाईदार परत माना जाना है। इसलिए, पिछड़े खंडों के भीतर 'मलाईदार परत' को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

(24) अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 3 में, यह था

उन्होंने कहा कि यह समझना होगा कि 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत केवल एक विशेष जाति के एक खंड को इस आधार पर बाहर करने के लिए पेश किया गया है कि वे आर्थिक रूप से उन्नत या शैक्षिक रूप से आगे हैं।उन्हें बाहर रखा गया है क्योंकि जब तक जाति के इस वर्ग को उस जाति समूह से बाहर नहीं रखा जाता है, तब तक पिछड़े वर्ग की उचित पहचान नहीं

हो सकती है।यदि क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता है, तो यह आसानी से कहा जा सकता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में शामिल की गई सभी जातियों को विशेष रूप से जाति के आधार पर शामिल किया गया है।यह आगे कहा गया कि 'मलाईदार परत' सिद्धांत को आरक्षण के सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू नहीं किया जाता है।इसका उपयोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के उद्देश्य से किया जाता है।स्थिति का सारांश देते हुए यह कहा गया कि अन्य बातों के साथ-साथ विवादित अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मलाईदार अन्य बातों के साथ साथत को बाहर रखा जाना चाहिए।इसके अलावा, वांछनीयता 3 (2008) 6 एस. सी. सी. 594 के रूप में समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए। अधिनियम के संचालन को जारी रखने के लिए।यह हर पाँच साल में एक बार किया जाना था।वास्तव में, इंद्र साहनी के मामले (ऊपर) में भी यह कहा गया था कि आरक्षण की योजना स्वयं सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा के अधीन है।जिस अवधि में समीक्षा की जानी थी, उसका अंतराल सरकार के अधिकार और विवेक के भीतर था, लेकिन निश्चित रूप से संवैधानिक मापदंडों और न्यायिक समीक्षा के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के अधीन था।अशोक कुमार ठाकुर के मामले (उपर्युक्त) में इसे दोहराया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई विवाद नहीं था और वास्तव में भारत संघ द्वारा उक्त मामले में यह उचित रूप से स्वीकार किया गया था कि

पिछड़े नागरिकों की आवधिक पहचान की आवश्यकता थी और इस उद्देश्य के लिए एक स्वीकार्य तंत्र के आधार पर पूरी आबादी के सर्वेक्षण की आवश्यकता थी।1931 की जनगणना में जो प्रासंगिक रहा होगा उसकी कुछ प्रासंगिकता हो सकती है लेकिन यह निर्धारक कारक नहीं हो सकता है।यह कहा गया था कि पिछड़ेपन को वस्तुनिष्ठ कारकों पर आधारित होना चाहिए जिसमें अपर्याप्तता तथ्यात्मक रूप से मौजूद होनी चाहिए।यह ध्यान दिया गया कि दुनिया में कहीं और जातियों, वर्गों या समुदायों ने पिछड़े दर्जे को प्राप्त करने के लिए कतार नहीं लगाई।दुनिया में कहीं और पिछड़ेपन का दावा करने और फिर यह दावा करने की प्रतिस्पर्धा नहीं थी कि वे दूसरे की तुलना में अधिक पिछड़े थे।

(25) इसलिए, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि 2016 के अधिनियम की अनुसूची III में उल्लिखित जातियों के पिछड़ेपन की पहचान के लिए एक अभ्यास किया गया था/किया जाना चाहिए। इसके अलावा, क्या 2016 के अधिनियम की अनुसूची III में उल्लिखित उक्त जातियां वास्तव में पिछड़ी हुई थीं।ऐसा प्रतीत होता है कि यह कवायद कानून के समक्ष नहीं की गई है और याचिकाकर्ताओं का यह कहना कुछ हद तक सही प्रतीत होता है कि प्रतिवादी के लिखित बयान के अनुसार, पिछड़े वर्गों का निर्धारण और पहचान न्यायाधीश के. सी. गुप्ता आयोग की रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिस पर राम सिंह के मामले (उपरोक्त) में भरोसा नहीं किया गया है।

(26) राम सिंह के मामले (उपरोक्त) में, भारत के राजपत्र में दिनांक 1 में प्रकाशित एक अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसके द्‌वारा जाट समुदाय को हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों के लिए पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया था।उक्त अधिसूचना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्‌वारा एन. सी. बी. सी. द्‌वारा दी गई सलाह को इस आधार पर अस्वीकार करने के लिए आई. डी. 1 पर लिए गए निर्णय के अनुसार जारी की गई थी कि उक्त सलाह में "जमीनी वास्तविकताओं को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखा गया था।"एन. सी. बी. सी. ने हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों की पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में जाटों को शामिल करने के लिए किए गए दावों का अध्ययन किया था।एन. सी. बी. सी. ने जाटों के लिए केंद्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश की। भरतपुर और धौलपुर जिलों को छोड़कर राजस्थान।जाटों को पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं करने के लिए एन. सी. बी. सी. की रिपोर्ट के खिलाफ विभिन्न विचार-विमर्शों और अभ्यावेदनों के बाद, जाट समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और गुजरात राज्यों में एक पूर्ण सर्वेक्षण करने के लिए आई. सी. एस. एस. आर. से संपर्क किया गया था।उक्त निर्णय एन. सी. बी. सी. को संबंधित राज्यों में ओ. बी. सी. की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए जाट समुदाय के अनुरोध पर विचार करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रात्मक डेटा की

आवश्यकता के कारण प्रेरित किया गया था।इसके बाद सरकार द्वारा इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया और एक कैबिनेट निर्णय लिया गया जिसमें एन. सी. बी. सी. को नमूना सर्वेक्षण करने के अपने पहले के फैसले पर पुनर्विचार करने और पहले से उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपनी सलाह देने के लिए कहा गया।हालाँकि, एन. सी. बी. सी. ने यह विचार रखा कि उसके पास इस मामले में पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं है और आई. सी. एस. एस. आर. से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वह इस विषय पर एक व्यापक साहित्य सर्वेक्षण आदेश के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करे ताकि आसन्न अभ्यास के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र की जा सके।आई. सी. एस. एस. आर. ने स्पष्ट रूप से पुस्तकों/साहित्य/प्रतिनिधित्व के माध्यम से अन्य सामग्रियों का कोई अध्ययन नहीं किया।आई. सी. एस. एस. आर. ने अपनी रिपोर्ट में कोई सिफारिश नहीं की, बल्कि केवल मौजूदा तथ्यों को निर्धारित किया।आई. सी. एस. एस. आर. की रिपोर्ट पर एन. सी. बी. सी. द्वारा विचार किया गया और इसने केंद्र सरकार को अपनी सलाह/राय/रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि जाट समुदाय ओ. बी. सी. की केंद्रीय सूची में शामिल करने के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। एन. सी. बी. सी. ने पाया कि जाट सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं थे।हालाँकि, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एन. सी. बी. सी. द्वारा दी गई सलाह पर निर्णय लिया कि एन. सी. बी. सी. ने "जमीनी वास्तविकताओं" को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखा।इसलिए,

मंत्रिमंडल ने उक्त सलाह को प्रतिग्रहण करना नहीं करने और इसके बजाय जाट समुदाय को हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों के लिए पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल करने का संकल्प लिया।हरियाणा राज्य में जाटों को विशेष ओ. बी. सी. के रूप में शामिल किया गया था। जहां तक हरियाणा का संबंध है, आई. सी. एस. एस. आर. के निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार हैः-

“हरियाणा उन राज्यों में से एक है जहाँ जाटों की बड़ी आबादी है।हमारी टिप्पणियां हरियाणा राज्य ओ. बी. सी. आयोग की रिपोर्ट पर आधारित हैं, जिसने 2012 में राज्य में ओ. बी. सी. के रूप में जाटों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी।आयोग ने अपनी सिफारिशें सांगवान (2012) द्वारा किए गए एक प्रायोजित अध्ययन पर आधारित कीं।अध्ययन के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि व्यावसायिक संरचना पर, हरियाणा में जाट एक जमींदार समुदाय हैं।लगभग 87 प्रतिशत जाट 596 में लगे हुए हैं। कृषि जाटों द्वारा अपनाई जाने वाली अन्य आर्थिक गतिविधियों में पशुपालन और व्यापार शामिल हैं।सरकारी रोजगार में, राज्य में कुल प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में जाटों की हिस्सेदारी लगभग 21 प्रतिशत है जो 2012 की जनसंख्या (25 प्रतिशत) में उनकी हिस्सेदारी से लगभग चार प्रतिशत कम है।हालाँकि, वे बिश्नोई और ब्राह्मणों की तुलना में पीछे हैं, जिनकी कक्षा I और II में सरकारी रोजगार में हिस्सेदारी उनकी संबंधित जनसंख्या हिस्सेदारी से अधिक है।

अहिर/यादव और गुजर (जाटों के साथ अन्य दो तुलनीय ओ. बी. सी. समुदाय) के लिए तुलनीय आंकड़े हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 2012 में दर्ज नहीं किए गए हैं।शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर, 1 वर्ष से कम आयु वर्ग के 12 प्रतिशत से अधिक जाट बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, जो कई अन्य पिछड़ी जातियों की तुलना में अधिक है।स्नातक स्तर पर जाटों का नामांकन लगभग 6.5 प्रतिशत है, जो 8.3 प्रतिशत के औसत स्तर से कम है।स्नातकोत्तर स्तर पर जाटों का नामांकन 1.71% है जबकि प्रतिवादी का औसत 2.26% है।इसलिए उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि हरियाणा में जाट जमींदार समुदाय हैं।प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सरकारी सेवा में उनका हिस्सा उनकी जनसंख्या के हिस्से के करीब है, लेकिन वे स्कूल और उच्च शिक्षा नामांकन दोनों में पीछे हैं।”

(27) उच्चतम न्यायालय ने आई. सी. एस. एस. आर. द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जो आठ विशिष्ट रिपोर्टों के अध्ययन पर आधारित थी जो मंत्री समूह द्वारा एन. सी. बी. सी. को एन. सी. बी. सी. के पहले के निर्णय की समीक्षा की मांग करते समय भेजी गई थी। जहाँ तक हरियाणा राज्य का संबंध है, न्यायाधीश वर्णम सिंह आयोग और न्यायाधीश के. सी. गुप्ता आयोग की रिपोर्टें प्रासंगिक थीं।जहाँ तक हरियाणा राज्य का संबंध है, एन. सी. बी. सी. की रिपोर्ट में प्रासंगिक निष्कर्ष निम्नानुसार हैंः- “एन. सी. बी. सी. ने पाया कि वर्ष 2012 के राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट (न्यायमूर्ति के. सी. गुप्ता आयोग की

रिपोर्ट) हरियाणा से संबंधित प्राथमिक दस्तावेज थी।एन. सी. बी. सी. ने उक्त रिपोर्ट में कुछ अंतर्निहित खामियां पाईं, जो उसके विचार में स्वीकार करने के योग्य नहीं थीं।उपरोक्त दृष्टिकोण रखने के लिए एन. सी. बी. सी. द्वारा दर्ज किए गए कुछ कारण हैंः

1) न्यायाधीश के. सी. गुप्ता आयोग की रिपोर्ट मुख्य रूप से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एम. डी. यू.), रोहतक द्वारा वर्ष 2012 में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है जो एक बहुत ही चयनात्मक अध्ययन था ।

2) न्यायाधीश गुप्ता के अलावा, आयोग में कम से कम दो अन्य व्यक्ति शामिल थे जो उन वर्गों/समूहों से संबंधित थे जो विचाराधीन थे अर्थात बिश्नोई और रोर जिन्हें अन्य पिछड़े वर्गों की राज्य सूची में शामिल किया गया था।

3) एम. डी. यू., रोहतक द्वारा किया गया सर्वेक्षण प्रो.के. एस. सांगवान जो जाट समुदाय से हैं; एम. डी. यू. के कुलपति भी जाट थे। आयोग द्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में, उपरोक्त दो व्यक्तियों पर पक्षपात का आरोप लगाया गया था।

4) एम. डी. यू. द्वारा किया गया सर्वेक्षण ब्राह्मणों, राजपूतों आदि जैसी उच्च जातियों के साथ जाटों का एक तुलनात्मक अध्ययन था और अहीरों, यादवों, कुर्मियों और गुर्जरों के संबंध में तुलनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं

थे।सार्वजनिक सुनवाई के दौरान यह पता चला कि उपरोक्त समुदायों यानी अहिर, यादव, कुर्मी और गुजर की तुलना में जाट श्रेष्ठ थे।

5) जिन गाँवों में सर्वेक्षण किया गया था, वे राज्य आयोग द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार थे और एम. डी. यू. द्वारा स्वतंत्र रूप से नहीं किए गए थे।

6) सशस्त्र बलों में जाटों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन नहीं किया गया था।

न्यायाधीश वर्णम सिंह आयोग की रिपोर्ट वर्ष 1990 की होने के कारण और पहले एन. सी. बी. सी. की रिपोर्ट 28.11.1997 पर प्रस्तुत करने के समय विचार किया गया था, जिसे एक बार फिर से विचार करने के लिए उचित नहीं माना गया था।एन. सी. बी. सी. ने दिशानिर्देशों, मानदंडों, प्रारूपों और मापदंडों का एक समूह विकसित किया था, जिसके खिलाफ अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में शामिल करने के सभी दावों पर विचार किया जाना आवश्यक है।उक्त मानदंड मंडल आयोग की रिपोर्ट और इंद्र साहनी के फैसले के आधार पर विकसित किए गए थे।11 तीन व्यापक शीर्षों यानी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक के तहत संकेतकों की पहचान की गई, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

ए. सामाजिक

(i) 598 द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़े माने जाने वाली जातियाँ/वर्ग

(ii) वे जातियाँ/वर्ग जो मुख्य रूप से अपनी आजीविका के लिए मामूली श्रम पर निर्भर हैं।

(iii) शहरी क्षेत्रों में, जहां राज्य के औसत से कम से कम 25 प्रतिशत महिलाओं और 10 प्रतिशत पुरुषों की शादी ग्रामीण क्षेत्रों में 17 वर्ष से कम उम्र में होती है और कम से कम 10 प्रतिशत महिलाओं और 5 प्रतिशत पुरुषों की शादी होती है।

(iv) ऐसी जातियाँ/वर्ग जहाँ कार्य में महिलाओं की भागीदारी राज्य के औसत से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक हो।

B. शैक्षिक

(v) ऐसी जातियाँ/वर्ग जहाँ 1 वर्ष से कम आयु वर्ग के ऐसे बच्चों की संख्या जो कभी स्कूल नहीं गए, राज्य के औसत से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक है।

(vi) ऐसी जातियाँ/वर्ग जहाँ कम से कम 1 वर्ष से कम आयु वर्ग में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की दर कम से कम हो।25%.राज्य के औसत से ऊपर।

(vii) ऐसी जातियाँ/वर्ग जिनके बीच मैट्रिक का अनुपात राज्य के औसत से कम से कम 25 प्रतिशत कम है।

ग. आर्थिक

(viii) ऐसी जातियाँ/वर्ग जहाँ पारिवारिक संपत्ति का औसत मूल्य राज्य के औसत से कम से कम 25 प्रतिशत कम हो।

(ix) जातियाँ/वर्ग जहाँ कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों की संख्या राज्य के औसत से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक है।

(x) जातियाँ/वर्ग जहाँ 50 प्रतिशत से अधिक घरों के लिए पीने के पानी का स्रोत आधा किलोमीटर से अधिक है।

(xi) जातियाँ/वर्ग जहाँ उपभोग ऋण लेने वाले परिवारों की संख्या राज्य के औसत से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक है।

उपर्युक्त तीन व्यापक शीर्षों के तहत प्रत्येक मापदंड के सापेक्ष वजन-आयु 3 के अनुपात में होनी चाहिएः2:1.न्यायाधीश के. सी. गुप्ता आयोग ने हालांकि 12 सामाजिक संकेतकों, 7 शैक्षिक संकेतकों और 5 आर्थिक संकेतकों का पालन किया।इसके अलावा, आयोग के अनुसार, पिछड़ेपन को निर्धारित करने की आवश्यकता थी, जो मुख्य रूप से सामाजिक पिछड़ेपन है, जो बदले में, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अन्य जातियाँ/वर्ग कैसे समझते हैं कि जाट सामाजिक रूप से पिछड़े थे या नहीं।न्यायाधीश के. सी. गुप्ता आयोग ने उपरोक्त दृष्टिकोण से मामले में आगे नहीं बढ़ाया।इसके अलावा अपनी रिपोर्ट में एन. सी. बी. सी. ने पाया कि सामाजिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, घर पर प्रसव आदि जैसे संकेतकों पर विचार किया गया

था।एन. सी. बी. सी. के अनुसार, इस तरह के आंकड़े वास्तव में सार्वजनिक स्वास्थ्य आंकड़े हैं और सामाजिक पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं। एन. सी. बी. सी. ने अपनी रिपोर्ट में के. सी. गुप्ता आयोग के विचारों के साथ अपनी असहमति भी दर्ज की कि जाट समुदाय से संबंधित 26 (90 में से) विधायक और संसद के 4 सदस्य (15 में से) होने के बावजूद जाटों ने सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से प्रगति नहीं की है।इस संबंध में, एन. सी. बी. सी. ने यह भी दर्ज किया था कि सार्वजनिक सुनवाई के दौरान यह पता चला कि हरियाणा के कई मुख्यमंत्री जो लंबे समय तक पद पर रहे हैं, वे जाट समुदाय से हैं और वास्तव में देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो जाट (चौधरी चरण सिंह)।”

(28) उअन्य बातों के साथ साथोक्त रिपोर्ट के अवलोकन से अन्य बातों के साथ-साथ पता चलता है कि न्यायाधीश वर्णम सिंह आयोग की रिपोर्ट वर्ष 1990 की है और जिस अन्य बातों के साथ साथ पहले एन. सी. बी. सी. की रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय विचार किया गया था, उसे एक बार फिर से विचार करने के लिए उचित नहीं माना गया था।इसके अलावा, यह भी उल्लेख किया गया है कि एन. सी. बी. सी. ने अपनी रिपोर्ट में न्यायाधीश के. सी. गुप्ता आयोग के विचारों के साथ अपनी असहमति भी दर्ज की।

(29) उच्चतम न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि निस्संदेह एन. सी. बी. सी. की दिनांक 1 की रिपोर्ट राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों की विभिन्न

रिपोर्टों, इस विषय पर उपलब्ध अन्य साहित्य और मामले की जांच के लिए आई. सी. एस. एस. आर. द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों पर विचार करने पर बनाई गई थी।विचाराधीन राज्यों की अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए जाटों की सिफारिश नहीं करने का निर्णय, जिसमें हरियाणा राज्य भी शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि इसे किसी भी सामग्री पर आधारित या कारणों से असमर्थित या किसी भी तरह से बाहरी और अप्रासंगिक मामलों पर विचार करने पर लिए गए निर्णयों के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

(30) राम सिंह के मामले (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि जहां तक हरियाणा का संबंध है, अपनाया गया परीक्षण 600 पर दिखाई दिया शैक्षिक रूप से पिछड़े होना।इसी तरह, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए भी, जाटों को शामिल करने के लिए शैक्षिक पिछड़ेपन को इस तथ्य के साथ निर्धारक कारक के रूप में ध्यान में रखा गया था कि जाट उन गुर्जरों के पीछे थे जो पहले से ही अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल थे। इसी तरह, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, परीक्षा शैक्षिक पिछड़ेपन के रूप में दिखाई दी; राजस्थान के संबंध में भी यही स्थिति थी।यद्यपि मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार राज्यों को भी विवादित अधिसूचना द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूचियों में शामिल किया गया था, लेकिन 2 मार्च, 2014 की मंत्रिमंडल की बैठक के कार्यवृत्त में इन राज्यों के मामलों पर कोई स्पष्ट विचार नहीं किया गया

था।बेशक, यह कहा गया था कि मंत्रिमंडल से प्रत्येक राज्य के बारे में अपने विचार के तरीके को दर्ज करने की उम्मीद की अनुपस्थिति में की जाती थी, लेकिन जब कुछ राज्यों के लिए ऐसा किया जाता है, तो अन्य राज्यों का कोई उल्लेख न होना इस निष्कर्ष पर पहुंचने का एक मजबूत आधार होगा कि जिन राज्यों का कार्यवृत्त में कोई उल्लेख की अनुपस्थिति में पाया गया, वास्तव में, उन्हें मंत्रिमंडल का विचार प्राप्त की अनुपस्थिति में हुआ।

(31) राम सिंह के मामले (उपरोक्त) में आगे कहा गया कि इस मामले में सरकार के निर्णय के अधिकार को निर्धारित करने के लिए एक बहुत ही मौलिक और बुनियादी परीक्षा यह होगी कि जाटों को अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल करने के खिलाफ एन. सी. बी. सी. की सलाह को गलत माना जाए और उसके बाद इस बात की जांच की जाए कि क्या इसके विपरीत केंद्र सरकार का निर्णय आवश्यक जांच में सफल होगा।उस आधार पर कार्यवाही करते हुए यह स्पष्ट था कि हरियाणा के मामले में राज्य आयोग की रिपोर्ट (न्यायमूर्ति के. सी. गुप्ता आयोग की रिपोर्ट) को छोड़कर, जो वर्ष 2012 में प्रस्तुत की गई थी, अन्य सभी रिपोर्टों के साथ-साथ इस विषय पर साहित्य भी कम से कम एक दशक पुराना होगा।जिन आवश्यक आंकड़ों पर अभ्यास किया जाना था, वे समकालीन होने चाहिए थे।ओ. बी. सी. की सूची में शामिल करने के उद्देश्य से पिछड़ेपन को मापने के लिए पुराने आंकड़े सटीक मापदंड प्रदान नहीं कर सके। ऐसा

इसलिए था क्योंकि कोई भी वैध रूप से सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा जैसे हर मोर्चे पर सभी नागरिकों की प्रगतिशील प्रगति का अनुमान लगा सकता है।कोई भी अन्य दृष्टिकोण शासन को प्रतिगामी करने के बराबर होगा।फिर भी, आश्चर्यजनक रूप से अदालत को देखने वाले तथ्यों ने इस तरह के नकारात्मक शासन की सरकारी पुष्टि का संकेत दिया क्योंकि जाटों को पिछड़े के रूप में नहीं मानने के दशक पुराने निर्णय, मौजूदा जमीनी वास्तविकताओं पर उचित विचार करने पर पहुंचे थे, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के बावजूद फिर से खोल दिए गए थे।इसे विवादित सरकारी निर्णय में अंतर्निहित बुनियादी भ्रांति माना गया था जिसे उक्त कार्यवाही में चुनौती दी गई थी।ओ. बी. सी. की अनुमानित जनसंख्या का प्रतिशत "52 प्रतिशत से कम नहीं" (इंद्रा साहनी) निश्चित रूप से यह कहा जाता था कि इसमें काफी वृद्धि हुई होगी क्योंकि पिछले दो दशकों में केवल केंद्रीय और साथ ही राज्य ओ. बी. सी. सूचियों में समावेश किया गया था और शायद ही कोई बहिष्कार किया गया था।यह निश्चित रूप से वह नहीं था जिसकी परिकल्पना संवैधानिक योजना में की गई थी।(32) जहाँ तक हरियाणा राज्य की समकालीन रिपोर्ट का संबंध है, उससे पहले की चर्चा ने उक्त रिपोर्ट के संबंध में एन. सी. बी. सी. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण और उसमें निहित निष्कर्षों को प्रतिग्रहण करना नहीं करने के लिए पर्याप्त और अच्छे कारणों का संकेत दिया।ऐसा ही कहा गया था कि शायद ही इसे और दोहराने की आवश्यकता होगी।

(33) इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि न्यायाधीश के. सी. गुप्ता आयोग की रिपोर्ट को एन. सी. बी. सी. द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, जिसे उच्चतम न्यायालय ने माना था कि शायद ही किसी और पुनरावृत्ति की आवश्यकता होगी।हालांकि, यह सवाल कि क्या इसे राज्य विधायी अधिनियम के लिए प्रासंगिक कहा जा सकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता होगी क्योंकि यह प्रतिवादी संख्या 1 और 2 का रुख है कि आयोग की रिपोर्ट एन. सी. बी. सी. के निष्कर्षों के आधार पर थी, जिसने आगे सर्वेक्षण का काम आई. सी. एस. एस. आर. द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति को सौंपा था और आई. सी. एस. एस. आर. की रिपोर्ट से पता चलता है कि जाट समुदाय स्कूल और उच्च शिक्षा नामांकन दोनों में पीछे था।

(34) इस संबंध में, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, सरकार द्वारा ही समय-समय पर समीक्षा की जानी है।यह कहा गया था कि जिस अवधि में इंदिरा साहनी के मामले (उपरोक्त) में समीक्षा की जानी है, वह सरकार के अधिकार और विवेकाधिकार के भीतर थी, लेकिन निश्चित रूप से संवैधानिक मापदंडों और न्यायिक समीक्षा के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के अधीन थी।वास्तव में इंद्र साहनी के मामले (उपरोक्त) में कहा गया था कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास ओ. बी. सी. की सूची में शामिल करने के अनुरोधों और अति-समावेश या गैर-समावेश की शिकायतों की जांच करने और सरकार को सलाह देने के लिए एक आयोग

की प्रकृति में एक स्थायी तंत्र बनाने की शक्ति है और उसे बनाना चाहिए, जो सलाह आम तौर पर सरकार के लिए बाध्यकारी थी।हालाँकि, जहाँ सरकार ने सलाह को प्रतिग्रहण करना नहीं किया, वहाँ यह कहा गया कि उसे इसके लिए अपने कारणों को दर्ज करना चाहिए।यह आगे कहा गया कि भले ही किसी नए वर्ग/समूह को अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया हो, ऐसे मामले को भी पहले उक्त निकाय को भेजा जाना चाहिए और उसकी सिफारिश के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए।निकाय आधिकारिक और गैर-आधिकारिक दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बना होना चाहिए, और एक उचित और प्रभावी जांच करने के लिए आवश्यक शक्तियों के साथ निहित होना चाहिए।यह समान रूप से वांछनीय था कि प्रत्येक राज्य एक ऐसे निकाय का गठन करे, जो वास्तविक 602 के निवारण में एक लंबा रास्ता तय करेगा। शिकायतें।ऐसा निकाय अनुच्छेद 16 के खंड (4) के तहत-या अनुच्छेद 340 के साथ पठित अनुच्छेद 16 (4) के तहत-नागरिकों के पिछड़े वर्ग की पहचान करने और निर्दिष्ट करने की शक्ति के सहवर्ती के रूप में बनाया जा सकता है, जिनके पक्ष में आरक्षण प्रदान किया जाना था।तदनुसार, एक निर्देश जारी किया गया कि निर्णय की तारीख से चार महीने के भीतर केंद्रीय स्तर और राज्यों के स्तर दोनों पर इस तरह के निकाय का गठन किया जाए।इन्हें तुरंत चालू किया जाना था और प्राप्त होने वाली शिकायतों और प्रकृति के मामलों, यदि कोई हो, की तुरंत सुनवाई और जांच करने की स्थिति में

होना था।यह भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के लिए खुला छोड़ दिया गया था कि वे इस तरह के निकाय द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को तैयार करें।ओ. बी. सी. की सूचियों के आवधिक संशोधन के मामले में इस प्रकार बनाए गए निकाय या निकायों से भी परामर्श किया जा सकता है। इसके अलावा, जैसा कि के. सी. वसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य 4 में सुझाव दिया गया था, इन सूचियों का समय-समय पर संशोधन किया जाना चाहिए ताकि उन लोगों को बाहर किया जा सके जो पिछड़े नहीं रह गए थे या नए वर्गों को शामिल किया जा सके, जैसा भी मामला हो।

(35) उक्त निर्देश के परिणामस्वरूप हरियाणा राज्य ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9) (जिसे इसके बाद-'बी. सी. आयोग अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) अधिनियमित किया है।उक्त बी. सी. आयोग अधिनियम 'उद्देश्यों और कारणों के विवरण' में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत प्रावधानों के अनुसार विभिन्न जातियों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के मुद्दे को हल करने के लिए हरियाणा सरकार ने न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री वर्णम सिंह की अध्यक्षता में अपना पहला पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया।आयोग की सिफारिशों पर, राज्य सरकार ने दिनांक 2 की अधिसूचना के माध्यम से दस जातियों, अहिर, बिश्नोई, मेव, गुर्जर, जाट, जाट सिख, रोर, सैनी, त्यागी और राजपूत को पिछड़े वर्गों की सूची

में शामिल किया और इन जातियों को 1 पर आरक्षण प्रदान किया।राज्य सरकार ने आरक्षण नीति की फिर से जांच की और 12.09.1991 पर आदेश जारी किया कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक 05.04.1991 पर जारी पत्र से पहले प्रचलित स्थिति के अनुसार भर्ती की जाएगी।

(36) इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से यह रहा है कि जाटों को आरक्षण के लाभों के हकदार जातियों में शामिल नहीं किया गया था।(37) बी. सी. आयोग अधिनियम के 'उद्देश्यों और कारणों के विवरण' में आगे कहा गया है कि दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिश पर, राज्य सरकार ने 07.06.1995 पिछड़ी जातियों की सूची में अहिर/यादव, गुर्जर, सैनी, मेव, लोध और लोढ़ा नाम की पाँच जातियाँ शामिल थीं।इसके अलावा आई. डी. 1 पर, पिछड़े वर्गों को दो ब्लॉक 'ए' और 'बी' में विभाजित किया गया और 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया, जिसमें 16 प्रतिशत ब्लॉक 'ए' और 11 प्रतिशत ब्लॉक 'बी' के लिए था।

(38) चूंकि राज्य सरकार को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने के लिए जाट, जाट सिख, रोर, त्यागी, बिश्नोई और मुल्ला जाटों/मुस्लिम जाटों सहित विभिन्न अन्य जातियों से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे थे, इसलिए हरियाणा सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 08.04.2011 के माध्यम से न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन किया। के. सी. गुप्ताआयोग

द्वारा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से किए गए अध्ययन के आधार पर, इसने आई. डी. 1 पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं और समूह 'सी' और 'डी' पदों में रोजगार में और इन जातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में दस प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की।समूह 'ए' और 'बी' में 28.02.2013 पर चार प्रतिशत आरक्षण भी प्रदान किया गया था (बाद में इसे बढ़ाकर 15.07.2014 पर पाँच प्रतिशत कर दिया गया)।इसके बाद उक्त निर्णय को इस न्यायालय में चुनौती दिए जाने का संदर्भ दिया गया है।इसके बाद यह सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम की तर्ज पर हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधानिक दर्जा दे सकती है, जिसकी सलाह आमतौर पर राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होगी।हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा भी इस मामले की जांच की गई और यह सुझाव दिया गया कि हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधानिक दर्जा देकर उसके गठन के लिए कदम उठाए जाएं।

(39) इस आशय का एक और उल्लेख किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 340 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों की जांच करने और उचित सिफारिशें करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है।इंदिरा साहनी के मामले (उपरोक्त) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को एक

आयोग या न्यायाधिकरण के रूप में एक स्थायी निकाय का गठन करने का निर्देश दिया था ताकि नागरिकों की ओ. बी. सी. की सूची में अति-समावेश और कम-समावेश की शिकायतों और अनुरोधों पर विचार, जांच और सिफारिश की जा सके।उपरोक्त प्रावधानों के तहत, राज्य सरकारों के पास उपरोक्त संदर्भित मुद्दों और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े मामलों की जांच करने और सरकार को सलाह देने के लिए आयोग की प्रकृति में एक स्थायी तंत्र बनाने की शक्ति है, जिसकी सलाह आम तौर पर सरकार पर बाध्यकारी होगी।

(40) उद्देश्यों और कारणों के बयान में आगे कहा गया है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश की मांग को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे।हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकार ने एक स्थायी तंत्र स्थापित करने और एक अलग कानून बनाकर हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधानिक दर्जा देने का निर्णय लिया।इसके अलावा, पिछड़े वर्गों के भीतर ब्लॉकों को शामिल करने, हटाने या बदलने की मांग भविष्य में भी विभिन्न समुदायों से उत्पन्न होने की संभावना थी।इसलिए, यह अनिवार्य हो गया था कि हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए।इन परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि हरियाणा बी. सी. आयोग का गठन बी. सी. आयोग अधिनियम के तहत किया गया है ताकि किसी भी वर्ग के नागरिकों को पिछड़े वर्ग के रूप में शामिल करने या बहिष्कृत

करने के अनुरोधों की जांच की जा सके और किसी भी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या उसके तहत शामिल करने की शिकायतों की सुनवाई की जा सके और राज्य सरकार को ऐसी सलाह दी जा सके जो वह उचित समझे।इसके अलावा, पिछड़े वर्गों का समय-समय पर संशोधन किया जाना चाहिए, जिसे राज्य सरकार किसी भी समय कर सकती है और बी. सी. आयोग अधिनियम लागू होने से दस साल की समाप्ति पर और उसके बाद हर दस साल की अवधि में पिछड़े वर्गों का संशोधन करेगी।

(41) हरियाणा राज्य ने 2016 का अधिनियम लागू किया है, हालांकि, यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक अभ्यास किया गया है कि क्या जाट एक पिछड़े वर्ग हैं।यह अभ्यास किया जाना चाहिए था/है और इंद्र साहनी के मामले (ऊपर) में यह जनादेश था।इसके अलावा, 2016 अधिनियम की खंड 13 में 'अनुसूची की समीक्षा', यानी 2016 अधिनियम 1 में संलग्न 'अनुसूचियों' का प्रावधान है।यह प्रावधान किया गया है कि सरकार उक्त 2016 अधिनियम के लागू होने के दस साल की समाप्ति पर और उसके बाद की प्रत्येक दस साल की अवधि में अनुसूची का संशोधन करेगी।इसके अलावा, बी. सी. आयोग अधिनियम की धारा 11 में 'पिछड़े खंडों के आवधिक संशोधन' का भी प्रावधान है।इसकी उप-धारा (1) में परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकार किसी भी समय और बी. सी. आयोग अधिनियम के लागू होने से दस साल की समाप्ति पर और उसके बाद की हर दस साल की अवधि में संशोधन कर सकती है। उप-धारा (2) में

प्रावधान है कि राज्य सरकार उप-धारा (1) के तहत कार्य करते हुए हरियाणा बी. सी. आयोग से परामर्श करेगी।

(42) याचिकाकर्ता इस आधार पर 2016 के अधिनियम को अमान्य करने की मांग करते हैं कि जाट समुदाय के पिछड़ेपन को निर्धारित करने की कवायद नहीं की गई थी।हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता जनहित याचिकाओं की प्रकृति में दायर याचिकाओं में 2016 के अधिनियम को अमान्य करने की मांग करते हैं। पी. आई. एल. को आम तौर पर किसी विधायी अधिनियम को अमान्य करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना चाहिए और उसे अपनाया जाना चाहिए।न्यायालयों को पी. आई. एल. में किसी अधिनियम के अधिकारों पर विचार करने में धीमी गति से और सावधानी और सावधानी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। जनहित याचिकाओं के माध्यम से, 2016 के अधिनियम के अधिनियमन पर ही हमला किया जाना चाहिए और इस आधार पर अमान्य कर दिया जाना चाहिए कि जिन जातियों को आरक्षण का लाभ दिया गया है, उनकी आवश्यक पहचान नहीं की गई है।हालाँकि, यह इस स्तर पर भी कानून को अमान्य करने की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है।विधायिका के एक विधायी अधिनियम को केवल पूछने पर अमान्य नहीं किया जाना चाहिए।

(43) सुब्रमण्यन स्वामी बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य 5 में, यह कहा गया था कि जहां है

विधायिका द्वारा अधिनियमित किसी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए, न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी अधिनियम की संवैधानिकता का हमेशा अनुमान होता है, और संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन दिखाया जाना चाहिए।विधायी प्रक्रिया की मौलिक प्रकृति और महत्व को न्यायालय द्वारा मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है और विधायी प्रक्रिया को उचित सम्मान और सम्मान दिया जाना चाहिए।जहां कानून को असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में चुनौती देने की मांग की जाती है, वहां न्यायालय को कानून के अमान्य होने के संबंध में अनुच्छेद 14 की प्रयोज्यता से संबंधित सिद्धांतों को याद दिलाना चाहिए।कानून बनाने और कानून को अमान्य बनाने के लिए अनुच्छेद 14 के दो आयाम अब अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त हैं और ये हैं (i) एक अस्वीकार्य या अमान्य वर्गीकरण के आधार पर भेदभाव और (ii) शक्तियों का अत्यधिक प्रत्यायोजन; कार्यपालिका को अप्रमाणित और निर्देशित शक्तियों का प्रदान करना, चाहे प्रत्यायोजित कानून के रूप में या प्रशासनिक आदेश पारित करने के लिए अधिकार प्रदान करने के माध्यम से-यदि ऐसा प्रदान किसी भी मार्गदर्शन, नियंत्रण या नियंत्रण के बिना है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। न्यायालय को यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि

कानून केवल इसलिए असंवैधानिक नहीं हो जाता है क्योंकि एक और दृष्टिकोण है या क्योंकि किसी अन्य विधि को सामाजिक, या यहां तक कि आर्थिक नीति के किसी भी मुद्दे की तरह अच्छा या उससे भी अधिक प्रभावी माना जा सकता है।यह अच्छी तरह से तय है कि अदालतें नीति क्या है, इस पर अपने विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करती हैं।

(44) राजबाला और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 6 में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस देश की अदालतें इस आधार पर किसी कानून के टुकड़े को असंवैधानिक घोषित करने का कार्य नहीं करती हैं कि कानून "मनमाना" है क्योंकि इस तरह की कवायद एक मूल्य निर्णय का तात्पर्य है और अदालतें विधायी विकल्पों के विवेक की जांच नहीं करती हैं जब तक कि कानून अन्यथा संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।यह आगे कहा गया कि इस तरह की जांच करने के लिए, भारतीय विधान की संवैधानिकता की जांच करते समय अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले के समय में नियोजित "मूल उचित प्रक्रिया" के सिद्धांत को वस्तुतः आयात करने के बराबर होगा।यह निष्कर्ष निकाला गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए किसी अधिनियम को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित करने की अनुमति नहीं थी कि यह 'मनमाना' है।

(45) इसलिए, 2016 के अधिनियम को अमान्य करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है, विशेष रूप से जब इस आधार पर हमला करने

की मांग की जाती है कि अनुसूची III में उल्लिखित जातियों के पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए मात्रात्मक डेटा एकत्र करने का अभ्यास नहीं किया गया है।यह अभ्यास इस स्तर पर भी किया जा सकता है।वास्तव में, अनुमत आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए, एम. नागराज बनाम भारत संघ 7 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यों को प्रशासन में दक्षता बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए वर्ग के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़ों की पहचान करनी होगी और उन्हें एकत्र करना होगा।यदि संबंधित राज्य इसे पहचानने और मापने में विफल रहता है, तो आरक्षण का प्रावधान अमान्य होगा।प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर आरक्षण की सीमा तय की जानी थी।

(46) एस. वी. जोशी बनाम कर्नाटक राज्य 8 में,

तमिलनाडु और कर्नाटक में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों को क्रमशः 69 प्रतिशत और 73 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले अधिनियमों पर इस आधार पर हमला किया गया कि उनमें आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक है उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह निर्धारण किया गया था कि क्या तमिलनाडु में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (राज्य के तहत शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 1993 वैध था। यह देखा गया कि उक्त मामले में

याचिकाएं दायर करने के बाद, संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 को क्रमशः संविधान (93वां संशोधन) अधिनियम, 2005 और संविधान (8वां संशोधन) अधिनियम, 2000 के माध्यम से संशोधित किया गया था।एम. नागराज के मामले (ऊपर) और अशोक कुमार ठाकुर के मामले (ऊपर) में उक्त संशोधन अधिनियम निर्णय का विषय रहे थे।उक्त मामले अन्य बातों के साथ साथ यह अन्य बातों के साथ निर्धारित किया गया था कि यदि कोई राज्य 50 प्रतिशत आरक्षण को पार करना चाहता है, तो उसे अपने निर्णय को मात्रात्मक आंकड़ों पर आधारित करना आवश्यक था, जो उक्त मामले अन्य बातों के साथ साथ नहीं किया गया था।तदनुसार, राज्य को तमिलनाडु राज्य पिछड़ा आयोग के समक्ष मात्रात्मक आंकड़े रखने का निर्देश दिया गया था और अन्य बातों के अलावा इस तरह के मात्रात्मक आंकड़ों के आधार पर आयोग आरक्षण की मात्रा तय करेगा।रिट याचिकाओं का निपटारा राज्य सरकार को फिर से दौरा करने और जो कहा गया था उसके आलोक में उचित निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया गया था।

(47) इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह न्यायसंगत और समीचीन होगा कि हरियाणा बी. सी. आयोग 2016 अधिनियम की अनुसूची III में उल्लिखित जातियों के लिए आरक्षण की सीमा, यदि कोई हो, और उनके लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक अभ्यास करे।विवादित कानून के अनुसरण में आरक्षण प्रदान करके 50 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन किए

जाने और क्या यह इतना उचित है, इस बारे में सवाल भी हरियाणा बी. सी. आयोग द्वारा उठाया और विचार किया जा सकता है।इस कवायद के लिए, राज्य सरकार हरियाणा बी. सी. आयोग के समक्ष अन्य बातों के अलावा मात्रात्मक डेटा रखेगी, इसके अलावा, हरियाणा बी. सी. आयोग स्वयं राज्य सरकार, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और/या किसी अन्य विभाग से कोई भी प्रासंगिक डेटा, जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।कोई भी इच्छुक या हितधारक इस संबंध में हरियाणा बी. सी. आयोग के समक्ष सामग्री रखने के लिए भी स्वतंत्र होगा।राज्य सरकार, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और/या कोई अन्य विभाग और कोई अन्य हितधारक या इच्छुक व्यक्ति 30.11.2017 द्वारा आयोग के समक्ष आरक्षण के पक्ष या विपक्ष में आंकड़े जमा कर सकते हैं।राज्य सरकार उक्त तिथि तक आयोग को डेटा जमा करने के लिए उचित और व्यापक प्रकाशन करेगी।प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को हरियाणा बी. सी. आयोग द्वारा अपने वेबसाइट पर रखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो डेटा पर कोई आपत्ति उठाना चाहता है, उसे 30.12.2017 द्वारा दाखिल करना होगा।हरियाणा बी. सी. आयोग अपनी रिपोर्ट 31.03.2018 द्वारा देगा।आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार कानून के अनुसार इस पर निर्णय लेगी।जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक 2016 अधिनियम की अनुसूची III में प्रास्थगन

वर्गों के लिए सेवाओं और प्रवेश में आरक्षण का लाभ स्थगित रखा जाएगा।

(48) हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सामान्य श्रेणी से संबंधित आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्रदान करने के संबंध में जो अन्य विवाद उठाए गए हैं, उनमें अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को शामिल नहीं किया जा रहा है।सरकारी, सरकारी उपक्रमों और स्थानीय निकायों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी अधिसूचना में सामान्य श्रेणी से संबंधित आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत तक आरक्षण है।प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती में सरकारी, सरकारी उपक्रमों और स्थानीय निकायों की नौकरियों में भी 4 प्रतिशत आरक्षण है।इसके अलावा, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण है, जहां प्रवेश में आरक्षण प्रदान किया जाता है।वर्तमान मामलों में सामान्य श्रेणी से संबंधित आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में तर्कों पर विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ चुनौती मुख्य रूप से 2016 अधिनियम की अनुसूची III के लिए रही है। इसके अलावा, अन्य संबंधित मामले, यानी 2013 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 2708,2013 का 15768,2014 का 2441,2014 का 6070 और 2014 का 13150, इस संबंध में लंबित हैं।इसलिए, उक्त मामलों में सामान्य श्रेणी से संबंधित आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को आरक्षण

प्रदान करने वाली दिनांकित 27.09.2013 अधिसूचना को अमान्य करने के लिए विवाद उठाना उचित और उचित होगा।

पूर्ववर्ती कारणों से,

(i) 2016 अधिनियम को बरकरार रखा गया है और बनाए रखा गया है;

((ख) तथापि, हरियाणा बी. सी. आयोग आरक्षण की सीमा, यदि कोई हो, जिसके लिए 2016 अधिनियम की अनुसूची III में उल्लिखित जातियां हकदार हैं, और उनके लिए प्रदान किए गए आरक्षण की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक अभ्यास करेगा।

(iii) राज्य सरकार हरियाणा बी. सी. आयोग के समक्ष अन्य बातों के अलावा, साथ-साथ मात्रात्मक आंकड़े रखेगी। इसके अलावा, हरियाणा बी. सी. आयोग स्वयं राज्य सरकार, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और/या किसी अन्य विभाग से डेटा, जानकारी, जो उसके लिए आवश्यक हो, लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) कोई भी हितधारक या कोई भी इच्छुक व्यक्ति इस संबंध में हरियाणा बी. सी. आयोग के समक्ष सामग्री रखने के लिए स्वतंत्र होगा।

(v) राज्य सरकार, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और/या कोई अन्य विभाग और कोई अन्य हितधारक या इच्छुक व्यक्ति हरियाणा बी. सी. आयोग के समक्ष 30.11.2017 द्वारा आरक्षण के पक्ष या विपक्ष में आंकड़े प्रस्तुत कर सकता है।

(vi) राज्य सरकार उक्त तिथि तक हरियाणा बी. सी. आयोग को डेटा जमा करने के लिए उचित और व्यापक प्रकाशन करेगी।

(vii) हरियाणा बी. सी. आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर रखा जाएगा।

(viii) कोई भी व्यक्ति जो डेटा पर कोई आपत्ति उठाना चाहता है, उसे 30.12.2017 द्वारा दाखिल करेगा;

(ix) हरियाणा बी. सी. आयोग अपनी रिपोर्ट 31.03.2018 द्वारा करेगा;

(x) राज्य सरकार, हरियाणा बी. सी. आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उस पर निर्णय लेगी; (xi) जब तक यह प्रास्थगन पूरी नहीं हो जाती, तब तक 2016 अधिनियम की अनुसूची III में पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं और प्रवेश में आरक्षण का लाभ स्थगित रखा जाएगा।

(49) रिट याचिकाओं का निपटान तदनुसार किया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्येश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

(नरेंदर)
ट्रांसलेटर
कोर्ट ऑफ़ श्री के. पी. सिंह,
एडिशनल सेशंस जज, भिवानी !